

भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3504
11.08.2025 को उत्तर के लिए

अनुदान सहायता योजना के अंतर्गत वृक्षारोपण

3504. श्री मुकेशकुमार चंद्रकांत दलाल:

क्या पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) अनुदान सहायता योजना की शुरुआत से इसके अंतर्गत वृक्षारोपण हेतु राज्यवार/संघ राज्यक्षेत्रवार और वर्षवार कितने हेक्टेयर भूमि कवर की जा रही है और तत्संबंधी व्यौरा क्या है;
- (ख) उक्त योजना के अंतर्गत रोपे गए पौधों और कवर किए गए कुल क्षेत्रफल का राज्यवार और वर्ष-वार व्यौरा क्या है और उनकी उत्तरजीविता तथा वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं/किए जा रहे हैं;
- (ग) उक्त योजना के अंतर्गत वृक्षारोपण और उनके अनुरक्षण के लिए प्रदान की गई वित्तीय सहायता का व्यौरा क्या है और स्वीकृत राशि गैर-सरकारी और स्वैच्छिक संगठनों को किस प्रकार वितरित की जाती है;
- (घ) उक्त योजना के अंतर्गत प्राप्त मापनीय परिणामों या पर्यावरणीय लाभों का व्यौरा क्या है; और
- (ङ) सरकार द्वारा इस योजना के अंतर्गत अधिक सहभागिता को प्रोत्साहित करने हेतु गैर-सरकारी संगठनों और स्थानीय समुदायों में जागरूकता बढ़ाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं या उठाए जाने हैं?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री

(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

- (क) और (ख): मंत्रालय चयनित भू-दृश्यों में वृक्षारोपण और पारिस्थितिकी-बहाली के लिए एक केंद्रीय प्रायोजित योजना राष्ट्रीय हरित भारत मिशन (जीआईएम) को लागू कर रहा है, जिसके लिए संबंधित राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों से पारस्परिक वित्तीय दायित्व की आवश्यकता होती है। जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना के तहत रेखांकित आठ मिशनों में से जीआईएम एक है। इसका उद्देश्य भारत के वनावरण की सुरक्षा, बहाली तथा वृद्धि करना और चयनित भू-दृश्यों में वन और गैर-वानिकी क्षेत्रों में वृक्षारोपण कार्यकलापों को शुरू करके जलवायु परिवर्तन के प्रति उत्तरदायी होना है। जीआईएम कार्यकलाप वित वर्ष 2015-16 में शुरू किए गए थे। अब तक, सत्रह राज्य अर्थात् आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक,

केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मिजोरम, ओडिशा, पंजाब, सिक्किम, उत्तराखण्ड, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और एक संघ राज्य क्षेत्र जम्मू और कश्मीर को हरित भारत मिशन के तहत शामिल किया गया है। हरित भारत मिशन के तहत वृक्षारोपण/पारि-बहाली निर्माण हेतु क्षेत्र का राज्यवार और वर्षवार विस्तृत विवरण **अनुलग्नक-1** में दिया गया है।

वृक्षारोपण की उत्तरजीविता दर और वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए, हरित भारत मिशन (जीआईएम) के तहत राज्य और केंद्र दोनों स्तरों की व्यवस्थाओं को शामिल करते हुए एक बहु-स्तरीय माध्यम से वृक्षारोपण की निगरानी की जाती है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र पौधों के जीवित रहने की दर का आकलन करने और खराब हुए पेड़ों के कारणों का दस्तावेजीकरण करने के लिए वृक्षारोपण स्थलों का वार्षिक भौतिक सत्यापन करते हैं। इसके अलावा, राज्य वन विभाग जीवित रहने की दर से संबंधित स्थल-विशिष्ट चुनौतियों का समाधान करने के लिए केंद्रित रखरखाव अभियान सहित सुधारात्मक माध्यमों पर ध्यान देते हैं। अपनी वार्षिक प्रगति रिपोर्ट के भाग के रूप में, राज्य मंत्रालय को वृक्षारोपण स्थलों की .kml फ़ाइलें और जियो-टैग की गई तस्वीरें भेजते हैं, जिनका उपयोग केंद्रीकृत सत्यापन और निगरानी के लिए किया जाता है।

- (ग) जीआईएम के तहत कार्यविधियाँ संयुक्त वन प्रबंधन समितियों (जेएफएमसी) की सक्रिय भागीदारी के माध्यम से चयनित भू-दश्यों में संचालित की जा रही हैं। हरित भारत मिशन के तहत राज्यों को जारी की गई धनराशि/प्रदान की गई वित्तीय सहायता का राज्यवार विवरण **अनुलग्नक-2** में दिया गया है।
- (घ) हरित भारत मिशन (जीआईएम) ने भारत के वन और वृक्षावरण की समग्र वृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार, वनावरण वर्ष 2015 में लगभग 794245.00 वर्ग किमी से बढ़कर वर्ष 2023 में 827356.95 वर्ग किमी हो गया है, जो लगभग 33111.95 वर्ग किमी की शुद्ध वृद्धि दर्शाता है। यह वृद्धि हरित भारत मिशन सहित राज्य और केंद्र, दोनों स्तरों पर किए गए विभिन्न वनरोपण और वन बहाली पहलों के कारण है।
- (ड.) मंत्रालय ने वृक्षारोपण के प्रति भावनात्मक और सामुदायिक जुड़ाव को प्रोत्साहन देने के लिए "एक पेड़ मां के नाम" अभियान को बढ़ाने हेतु स्थानीय समुदायों में जागरूकता और भागीदारी को प्रोत्साहित करने की पहल की है। मंत्रालय बेहतर पहुँच और पारदर्शिता हेतु युवाओं और शहरी गैर-सरकारी संगठनों सहित अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने के लिए, मेरीलाइफ पोर्टल और अन्य सोशल मीडिया जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी उपयोग कर रहा है।

'अनुदान सहायता योजना के अंतर्गत वृक्षारोपण' के संबंध में श्री श्री मुकेशकुमार चंद्रकांत दलाल द्वारा दिनांक 11.08.2025 को उत्तर के लिए पूछे गए लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3504 के भाग (क) तथा (ख) के संदर्भ में उल्लिखित अनुलग्नक

हरित भारत मिशन के तहत वृक्षारोपण/पारिस्थितिकी बहाली हेतु शामिल किए गए क्षेत्र का राज्यवार और वर्षवार विवरण:

(क्षेत्रफल हेक्टेयर में)

क्र. सं.	राज्य	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	वृक्षारोपण/पारिस्थितिकी-बहाली का पूर्ण सूजन
1	आंध्र प्रदेश	0	534	0	0	0	899	0	0	0	0	1,433
2	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0	4,412	902	5,314
3	छत्तीसगढ़	19,128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,128
4	हरियाणा	0	0	0	0	0	0	0	1,301		0	1,301
5	हिमाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	574	556	169	1,299
6	जम्मू और कश्मीर	0	0	0	0	0	0	951	115	712	0	1,778
7	कर्नाटक	760	0	0	600	0	560	405	397	0	0	2,722
8	केरल	0	2,762	6,253	0	631	2,171	480	0	0	0	12,297
9	मध्य प्रदेश	0	0	0	10,554	8,236	680	0	7,127	6,234	0	32,831
10	महाराष्ट्र	0	0	0	5,223	0	0	0	0	0	0	5,223
11	मणिपुर	8,798	0	0	0	0	2,942	2,692	0	0	2,056	16,488
12	मिजोरम	0	19,643	0	0	0	0	0	0	0	0	19,643
13	ओडिशा	2,178	21	21	6,965	7,450	1,473	2,603	0	0	0	20,711
14	पंजाब	0	1,286	1,732	0	0	1,100	875	1,575	0	0	6,568
15	सिक्किम	0	0	0	1,509	0	0	2,474	2,584	0	0	6,567
16	उत्तराखण्ड	0	0	0	7,483	0	0	1,706	3,297	2,350	0	14,836
17	पश्चिम बंगाल	0	0	0	0	0	0	995	1,611	0	0	2,606
18	उत्तर प्रदेश*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
कुल		30,864	24,246	8,006	32,335	16,317	9,825	13,181	18,581	14,264	3,127	1,70,745

*जीआईएम क्रियाविधियां वर्ष 2024-25 में शुरू की गई और राज्य ने चालू वित्तीय वर्ष में केवल सूजन/वृक्षारोपण क्रियाविधियों को शुरू करने के लिए अग्रिम कार्य किया है।

'अनुदान सहायता योजना के अंतर्गत वृक्षारोपण' के संबंध में श्री श्री मुकेशकुमार चंद्रकांत दलाल द्वारा दिनांक 11.08.2025 को उत्तर के लिए पूछे गए लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3504 के भाग (ग) के संदर्भ में उल्लिखित अनुलग्नक

वित्त वर्ष 2015-16 से अब तक हरित भारत मिशन के तहत जारी धनराशि का राज्यवार विवरण:

(रुपये करोड़ में)

क्र.सं.	राज्य	जारी की गई कुल निधि
1	आंध्र प्रदेश	6.19
2	अरुणाचल प्रदेश	34.71
3	छत्तीसगढ़	72.84
4	हरियाणा	47.73
5	हिमाचल प्रदेश	17.09
6	जम्मू और कश्मीर	36.72
7	कर्नाटक	23.66
8	केरल	41.88
9	मध्य प्रदेश	123.26
10	महाराष्ट्र	10.30
11	मणिपुर	65.72
12	मिजोरम	160.21
13	ओडिशा	88.37
14	पंजाब	26.95
15	सिक्किम	42.73
16	उत्तराखण्ड	167.59
17	पश्चिम बंगाल	10.95
18	उत्तर प्रदेश	5.43
कुल		982.34
